



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2009/आषाढ़ 16, 1931

No. 235]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2009/ASADHA 16, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुल्कात अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2009

(निर्णायक समीक्षा)

सं. 15/34/08-डीजीएडी.—यतः, 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एकिलिक फाइबर (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश से संबंधित समीक्षा जांच के संबंध में अपने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10-11-2004 की अधिसूचना सं. 15/04/2003-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किए थे। मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 7-01-1998 को शुरू की गई थी और दिनांक 24-12-1998 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 32/1/97-एडीडी द्वारा इटली, स्पेन, पुर्तगाल तथा जापान पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। तथापि, पहली निर्णायक समीक्षा में केवल जापान पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की गई थी। निष्कर्षों के आधार पर राजस्व विभाग ने दिनांक 21-12-2004 की

अधिसूचना सं. 114/2004-सी.शु. द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था।

और, यतः, प्राधिकारी ने दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 14/5/2003 द्वारा पाटनरोधी जांच के अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे और बेलायस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एकिलिक फाइबर के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी। निष्कर्षों के आधार पर राजस्व विभाग की दिनांक 30-12-2004 की अधिसूचना सं. 117/2004 द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था।

2. समीक्षा हेतु अनुरोध

यतः, सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले वापस न लिया जाए तो ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

और, यतः, उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी से घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रमाण सहित किए गए विधिवत् अनुरोध के आधार पर इस उपाय की समाप्ति के पहले समुचित अवधि के भीतर यह समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या शुल्क समाप्त हो जाने से पाटन व क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

और, यतः, उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार फोरम ऑफ एकिलिक फाइबर मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली ने सहभागी कंपनियों यथा मैसर्स इंडियन एकिलिक्स लि., मै. वर्धमान एकिलिक्स लि. एवं मै. पशुपति एकिलॉन लि. के माध्यम से प्राधिकारी से संपर्क

किया है और अपेक्षित सूचना युक्त एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए निर्णायक समीक्षा का अनुरोध किया है। अतः प्राधिकारी यह समझते हैं कि पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए ऐसे शुल्क का अधिरोपण जारी रखने की आवश्यकता जांच करने और यह जांच करने कि शुल्क को हटाए जाने अथवा परिवर्तित किए जाने अथवा दोनों स्थितियों में क्या क्षति जारी रहने अथवा उनका पुनरावृत्ति होने की संभावना है; लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा कार्यवाही की शुरुआत करना समुचित है।

3. समीक्षा हेतु आधार

यह अनुरोध, लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने अथवा उसे बढ़ाने के लिए किया गया है। अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि आयात अभी भी जारी हैं जो परिस्थितियां मूल जांच के समय भी, आज की तारीख में भी वे अस्तित्व में हैं। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो यह प्रदर्शित करता है कि पाटन उसी वर्धित स्तर पर होता रहेगा, जिस स्तर पर यह मूल जांच के समय था। आवेदक ने इसके अलावा यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से लगातार हो रहे पाटन एवं परिणामतः क्षति का सामना कर रहा है और यह विश्वास करने का कोई कारण अथवा औचित्य नहीं है कि शुल्क वापस ले लिए जाने की परिणति पाटन की भारी मात्रा में वृद्धि एवं पुनरावृत्ति में होगी तथा परिणामतः घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचेगी।

4. जांच शुरुआत

वर्ष 2006 की रिट याचिका सं. 16893 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है, प्राधिकारी यह जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त हो जाने से पाटन व क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9(5) के अनुसरण में समीक्षा की एतद्वारा शुरुआत करते हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच तथा इस समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला होती है जो भार के अनुसार कम से कम 90% एक्रिलोनइट्रिल यूनियन से मिलकर बनती है। एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो अथवा एक्रिलिक टॉप हो सकता है। एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो अथवा एक्रिलिक टॉप को वाणिज्यिक भाषा में एक्रिलिक फाइबर कहा जाता है। एक्रिलिक स्टेपल फाइबर और एक्रिलिक टो में अंतर केवल लंबाई का होता है। यदि लंबाई 2 मीटर से अधिक होती है तो इसे टो कहा जाता है और कम लंबाई को स्टेपल फाइबर कहा जाता है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-1 के शीर्ष 550130 तथा 550330 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

मूल जांच में जिस उत्पाद की जांच की गई थी वह एक्रिलिक फाइबर था; अतः, इस समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का दायरा भी वहीं होगा।

6. प्रक्रिया

(I) जांच द्वारा यह निर्धारण किया जाएगा कि क्या उपायों की सम्पत्ति की परिणति पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति में होगी। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए शुल्क का अधिरोपण जारी रखना जरूरी है और क्या शुल्क को हटाए जाने अथवा उसमें संशोधन किए जाने अथवा दोनों किए जाने से क्षति की पुनरावृत्ति संभावित है।

- (i) समीक्षा में दिनांक 10-11-2004 की अधिसूचना सं. 15/4/2003-डीजीएडी तथा दिनांक 7-12-2004 की अधिसूचना सं. 14/5/2003-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
- (ii) इस जांच में शामिल देश जापान और बेलारूस हैं।
- (iii) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 है। तथापि, क्षति की जांच की अवधि अप्रैल, 2005-मार्च, 2006, अप्रैल 2006-मार्च, 2007, अप्रैल 2007-मार्च, 2008 एवं जांच अवधि होगी।
- (iv) इस समीक्षा में उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 एवं 20 आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

II. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, भारत स्थित दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों/प्रतिनिधियों, आयातकों तथा भारत में ज्ञात प्रयोक्तृओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रारूप तथा तरीके से अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग,

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय) (डीजीएडी),
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

फैक्स: 91-11-23063418

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित अपना निवेदन निर्धारित प्रारूप व तरीके से निम्नलिखित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर निवेदन करने वाले किसी भी पक्षकार से अन्य पक्षकारों हेतु उसका अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

III. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना अथवा सुनवाई हेतु किया गया कोई भी निवेदन प्राधिकारी को लिखित में इस प्रकार भेजा जाए ताकि वह उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के पत्र की तारीख से चालीस (40) दिन से अनधिक अवधि के भीतर प्राप्त हो जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में अपने जांच परिणाम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज कर सकते हैं।

IV. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा प्रस्तुत नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उन्हें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझते हों।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2009

(Sunset Review)

Subject: Sunset review of anti-dumping duty imposed on Acrylic Fibre originating in or exported from Japan and Belarus.

No. 15/34/08 -DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as ADD Rules), vide Notification Number 15-04-2003-DGAD, dated 10-11-2004, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings in the review investigation recommending continuation of anti-dumping duty on import of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Japan. The original anti-dumping investigation was initiated on 7-01-1998 and definitive anti-dumping duty was recommended vide final findings Notification No. 32/1/97-ADD, dated 24-12-1998 on Italy, Spain, Portugal and Japan.

However, in the first sunset review, the continuation of anti-dumping duty was recommended only from Japan. On the basis of findings, definitive anti-dumping duties were imposed on the subject goods by the Department of Revenue vide notification No. 114/2004-Cus., dated 21-12-2004.

And whereas the Authority vide Notification No. 14-5-2003, dated 7th December, 2004 notified its final findings in anti-dumping investigation recommending definitive anti-dumping duty on imports of Acrylic Fibre originating in or exported from Belarus. On the basis of findings, the definitive anti-dumping duties were imposed on the subject goods by the Department of Revenue vide Customs Notification No. 117/2004, dated 30-12-2004.

2. Request for Review

Whereas in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

And, whereas, notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

And, whereas, in terms of the above provisions, the Forum of Acrylic Fibres Manufacturers, New Delhi through the participating companies, viz., M/s. Indian Acrylics Ltd., M/s. Vardhman Acrylics Ltd. and M/s. Pasupati Acrylon Ltd. has approached the authority with an application containing information, requesting for sunset review, the Designated Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the Anti-Dumping Duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied or both.

3. Grounds for Review

The request is for continuation and enhancement of the anti-dumping duty in force. The request is based on the grounds that imports are still continuing. The circumstances which were prevalent at the time of original investigations are very much in existence till date. There has been no change in circumstances, which only reflects that the dumping would recur at the same aggravated level at which it was at the time of original investigation. The applicant has further argued that the domestic industry is facing continued dumping and consequent injury from subject countries and there is no reason or justification to believe that revocation of the duty would lead to increased or continued dumping and at large scale with consequent severe injury to the domestic industry.

4. Initiation

In view of judgement of Hon'ble Delhi High Court in WP No. 16893 of 2006 holding that sunset review is mandatory, the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. Product under Consideration

The product involved in the original investigation and this sunset review is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units. Acrylic Fibre can be acrylic staple fibre, acrylic tow or acrylic top. Acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance. The only difference between acrylic staple fibre and acrylic tow is the difference in length. In case of length more than 2 meters, it is known as tow and in case of cut lengths, it is known as staple fibre. It is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975. It is further classified under the heading 550130 and 550330 of Schedule-I of Custom Tariff Act. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

The product investigated in the original investigation was Acrylic Fibre therefore; the scope of the product under consideration in this review would remain same.

6. Procedure

(I) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- (i) The review will cover all aspects of Notification No. 15-4-2003-DGAD, dated 10-11-2004 and of Notification No. 14-5-2003-DGAD, dated 07-12-2004.
- (ii) The countries involved in this review investigation are Japan & Belarus.
- (iii) The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st January, 2008 to 31st December, 2008. However, for the injury examination, the period is April 2005—March 2006, April 2006—March 2007, April 2007—March, 2008 and POI

- (iv) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

(II) Submission of Information :

The exporters in subject countries, their governments through embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their view known to the Authority in the following address :

The Designated Authority

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

Udyog Bhawan, New Delhi-110011.

Fax : 91-11-23063418

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

(III) Time Limit :

Any information relating to the present sunset review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Sunset Review Notification. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

(IV) Inspection of Public File :

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority